teachers in the Delhi High Court. Was it not incumbent on the Delhi University and the authority to have this question decided prior to the filing of the writ, especially when there was a time lag between the original position and the date of filing of the writ which is 9th of January this year?

PROF. S. NURUL HASAN: The letter from the University Grants Commission to the various universities Communicating the scheme is dated the 13th August. In this letter, it was stated that detailed schemes were to be submitted by the universities towards the end of November or December. The representation from Delhi teachers was forwarded by the Vice-Chancellor to the University Grants Commission *vide* his letter dated January 1, 1976. You will see that between January 1 and January 9, not all the time had elapsed.

Loss due to devastating floods in Patna

*87 SHRI RAMAVATAR SHASTRI Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the loss to the tune of crores of rupees was caused in Patna town by the devastating floods in August last;

(b) if so, official as well as non-official estimates of the devastation caused;

(c) whether Government have formulated a scheme to find out a solution to the problems of the flood-affected people of Patna town; and

(d) if so, the salient features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) According to the reports received from the State Government, the tentative estimated damage to State Government Departments and public utilities is about Rs. 10.15 crores. The final figures are still under compilation. The State Government have also reported that damage to private properties has not been assessed but this is likely to be several crores of rupees. In addition to this, valuable documents in some libraries and office records have been damaged, which are not amenable to being assessed in monetary terms.

(c) and (d). Immediately after the floods, a High Level Expert Committee was set up by the Bihar Government to enquire into the Patna floods of August, 1975 and to suggest measures for future protection against similar catastrophies. The Committee is headed by Member (Floods), Central Water Commission and consists of the Chairman, Ganga Flood Control Commission, two Chief Engineers of the State Government Irrigation Department and two Members of the Bihar Legislative Assembly. The Committee submitted its interim report in November 1975 recommending flood protection and drainage works which have to be taken up on a priority basis. Its final report is awaited.

The main items of works, recommended by the Committee to be taken up on first priority are:—

(i) Construction of an embankment/masonary wall on the south bank of Ganga from Digha to Maner alongwith revetment at vulnerable places;

(ii) construction of a new embankment from Maner to Saidabad along the right bank of Sone;

(iii) construction of an escape channel from Patna canal upstream of Naubatpur through Khajuri distributary and Panchahua Nalla;

(iv) raising and strengthening of Danapur distributary; and

(v) improving and remodelling the existing urban drainage in Patna

The Commitee has also recommended that the remodelling of the drainage system in the rural areas and raising and strengthening of the left embankment of Punpun along with construction of new embankments in its upper reaches to be taken up as works of second priority

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस साल के अन्त में पटना में जैसी सत्यानाशी बाढ आई उस से जो नुकसान हुआ है उस के बारे में सरकार ने अपने वक्तव्य में दिया है कि अभी फिलहाल सवा दस करोड का सरकारी नुकसान होने का अनुमान है और जनता को कितना नुकसान हुआ है उस का पता लगाया जा रहा है। जाहिर बात है कि वह भी कम से कम उतना तो जरूर ही हुआ होगा। यानी 20-25 करोड रुपये का नुकसान हुआ है। इस पृष्ठभूमि में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि पटना में यादानापुरम 23-24 अगस्त को बाढ आने के पहले संभवत 21 अगस्त को मध्य प्रदेश की सरकार ने बिहार सरकार को आगाह कर दिया था कि यहां से पानी जा रहा है आप सावधान हो जाइए ईस के बावजद बिहार सरकार ने कोई बन्दोबस्त नहीं किया जिस के कारण इस विपत्ति का सामना वहां के नागरिकों को और सरकार को स्वयं करना पडा ? क्या यह संभव नहीं था कि पटना शहर को बचाया जा सकता था बशर्ते कि सरकारी अधिकारी मुस्तैदी दिखाते और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो उन्हें आगाह किया था उस पर ध्यान देते ? ऐसा नहीं करने की वजह से ही क्या इस तरह की विपत्ति वहां आई ?

श्री केदार नाथ सिंह : पटना में जो बाढ़ आई थी बहुतहत भयंकर थी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी सिलसिले में बिहार सरकार ने एक आयोग का गठन किया है और ये सारे मसले उस के सामने है। उस की रिपोर्ट आने के बाद इस पर बहस की जा सकती है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने पूछा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आगाह किया था या नहीं, इस में रिपोर्ट की क्या अपेक्षा है ? अगर आगाह किया था तो कहिए किया था और नहीं किया था तो कहिए नहीं किया था।

दूसरी बात—सरकार ने वक्तव्य में यह भी कहा है कि फला फला कमेटी ने अस्थायी सिफारिश की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी ने जो सिफारिशें दी है उन सिफारिशों को कार्य में लाने के लिए कौन से कदम अब तक उठाए गए हैं ताकि अगले मई जून और जुलाई में फिर बाढ न आने पाये और क्या बिहार सरकार ने इस के लिए भारत सरकार से किसी निश्चित राशि की मांग की है ? क्या यह बात भी सच है कि अभी हाल में बिहार विधान सभा के सभी दलों के कुछ प्रमुख सदस्यों का कोई प्रतिनिधि मंडल आया था ? वह प्रतिनिधि मंडल भी सिंचाई मंत्री से मिला था और उस ने भी कुछ सिफारिश आप के सामने की है या स्मरण-पत्र आप को दिया है ? यदि हां तो वह क्या था ? बिहार को और पटना को बाढ़ से बचाने के बारे में यदि इन की कोई सिफारिश है तो वह क्या है और उस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ताकि हम यह आश्वस्त हो सकें कि अगले साल पटना के निवासियों को ऐसी सत्यानाशी बाढ़ का मुकाबिला नहीं करना पडेगा ?

श्री केदार नाथ सिंह : इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि यह जो भयंकर बाढ़ इस वर्ष थी वह फिर अगले साल रिपीट

न हो, इस के सिलसिले में कदम उठाए जा रहे है और समिति ने जो पहली रिपोर्ट दी उस में उस ने साढ़े आठ करोड रुपए की मांग की है जिस में ढाई करोड रुपये का प्रबन्ध कर दिया गया है । उन से कहा गया है कि 31 मार्च तक उस रुपये को खर्च कर दे और जो उस की रेकमेंडेशस है उन को कार्यान्वित करे ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : बाढ के सबध में पूर्व जानकारी दी गई या नही मैं इस पचडे में पडना नही चाहता लेकिन यह स्पष्ट कहना चाहता हू कि यह जो बाढ थी वह बहुत ही भयकर प्रलयकारी और रोमाचकारी थी और इस से बिहार की बहुत बरबादी हुई । सरकार का जो जवाब स्टेटमेंट के रूप में है उस मे बहुत सारी बातों की चर्चा है कि बिहार में तत्काल क्या करना है और लोग टर्म में पटना के बचाव के लिए क्या काम करना है । इसी सन्दर्भ मे मै जानना चाहता हू कि क्या मत्री महोदय को यह जानकारी है कि अभी फिनहाल सर्वदलीय सहज समन्वय समिति बनी थी तो उस ने साढे तेरह करोड रुपये की मांग की है और क्या यह बात भी सच है कि बिहार सरकार ने योजना के नाम पर पटना के बचाव के लिए 189 करोड रुपये की मांग की है ? यदि हा तो इस सबध म सरकार का क्या विचार है और सरकार क्या करने जा रही है ?

कृषि तथा सिचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) बिहार से सदस्य लोग आए थे । सदस्य महोदय को मालूम है कि छठवे फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार, राज्यों में इस तरह की जो आधुनिक दुर्घटना होती है उस सबध के काम को उन के प्लान के अंदर ही किया जाता है । ये लोग यह कहने के लिए आए थे कि बिहार की ऐसी स्थिति नहीं है कि ऐसा किया जा सके । बाढ़ के नियत्रण के लिए जितने रुपये की आवश्यकता होगी वह यदि बिहार सरकार के प्लान से लिया जाय तो बिहार का सारा विकास का काम रुक जायगा । वे लोग हम से भी मिले थे, जैसा उन लोगों ने बतलाया वे लोग प्रधान मत्री से भी मिले थे और वित्त मंत्री से भी मिले थे । इस बारे मे इस प्रश्न पर विचार करना जरुरी होगा कि छठवे फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश है उस मे कुछ तबदीली कर के बिहार की मदद की जाय या नही ।

श्री गेंदा सिंह : मै तो यह समझता हूं कि पटना की बाढ केवल बिहार की ही नहीं थी उत्तर प्रदेश की बडी नदियों और मध्य प्रदेश की बडी नदियों की बाढ ने पटना में प्रलय का दृश्य उपस्थित किया था और उस समय जगजीवन राम जी, पटना और गोरखपुर गए थे । जब वह गोरखपुर गए थे तो उन से प्रतिनिधियों ने कुछ निवेदन किया था, ग्रुप से कोई बात छिपी नही है, सौभाग्य से जगजीवन राम जी के हाथ में वह पोर्ट फोलियो है और उन के जमाने मे पटना में यह घटना घटी । उसी समय उनका ध्यान दिला गया था कि गडक, राप्ती, घाघरा, गगा और सोन ये सब नदिया पटना के लिए विनाशकारी बाढ का कारण है, क्या इन के लिए कोई बन्दोबस्त किया जायगा ? तो जगजीवन बाबू ने उस वक्त कहा था कि हम कोई बन्दोबस्त इस सबध मे जरूर करेंगे । यह मामला बहुत गभीर है । अगर इन नदियो को काबू मे नही किया गया तो उत्तर भारत मे बिहार को और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को जो क्षति पहुंचती है उस क्षति को आसानी से दूर नही किया जा सकता । इस एमरजेन्सी के समय में मैं समझता हू कि उस को पहले ध्यान में आना चाहिए और अगर इस एमरजेन्सी में भी उस काम को सम्भाला नही गया तो बड़ा कठिन हो जायगा । क्या इस सबध में वयोवृद्ध खेती मंत्री जगजीवन राम जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सहाय पांडे : । वयोवृद्ध नहीं हैं ।

श्री गंदा सिंह : अब मैं क्यों कहूं कि वयोवृद्ध नहीं है । मेरी उम्र से तो उनकी उम्र ज्यादा ही है और मैं हमेशा उनको वयोवृद्ध मानता हू ।

श्री जगजीवन राम : श्री गेंदा सिंह ने एक वृहद प्रश्न उठाया है । इस में कोई संदेह नहीं है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से आती हैं और उन की धारा बहुत तेज होती है । जब बाढ़ आती है तो इन का भयंकर रूप हो जाता है । लेकिन इस का उपाय नेपाल के साथ बातचीत कर के ही किया जा सकता है और जैसा कि सदन को मालूम है इस संबंध में नेपाल के महाराजा से भी चर्चा हुई थी और उन के मंत्रियों से भी चर्चा हुई है कि अधिकांश नदियों के बारें में दोनों देशों के माहिर लोग इस मामले को देखें कि किन-किन नदियों को दोनों एक साथ मिल कर नियंत्रित करने का काम कर सकते हैं जिस में बाढ़ का नियंत्रण हो सके, सिंचाई का काम भी लिया जा सके और बिजली उत्पादन का भी काम किया जा सके । मैं समझता हूं कि उस दिशा में कुछ प्रगति हुई है दोनों देशों के प्रतिनिधि मिल कर विचार करेंगे कि किन-किन योजनाओं से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है ।

Preparations for participation in Montreal Olympic

*89. SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether preparations have been made by the Indian Olympic Association for participation of Indian team in the Montreal Olympic this year; and

(b) whether his Ministry has permitted the Indian Football team to participate in the pre-Olympic Games?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Preliminary discussions between the Indian Olympic Association and the All India Council of Sports about India's participation in the Olympic Games 1976 have been held. According to mutually agreed criteria for participation of Indian teams, only the Hockey Team would clearly qualify. A programme for its training has been initiated.

In addition, a few outstanding athlets, who reach reasonable standards after undergoing further training, as per programme already started, would also be permitted.

The All India Council of Sports has given careful consideration to the question of participation of the Indian Football Team in the Olympic Games, in consultation with the Indian Olympic Association, and have not recommeded the same.

The Indian Football Team has been participating in the pre-Olympics since 1964, and has not even once qualified from the Asian Zone. In the Asian Games held at Tehran in 1974, the Indian Football Team lost badly all the three matches it played. The All India Council of Sports, has, therfore, also not recommended its participation in the forthcoming pre-Olmpic Tournament.

The deterioration in the standard of football is causing serious concern to the Government of India. Government will take necessary action in the matter in consultation with the All India Council of Sports, Indian Olympic Association and the All India Football Federation.

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: In this long statement, the reasons for not allowing the Indian